संपादकीय

चुनावी हिंसा का सच सामने आये

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद हुई हिंसा में जघन्य अपराधों की बाबत राज्य सरकार की उदासीनता के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट के दखल के बाद सच्चाई सामने आने की उम्मीद जगी है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने चुनावी हिंसा के जघन्य मामलों की जांच सीबीआई को सौंपी है तो अन्य हिंसा व आगजनी के मामलों की जांच के लिये राज्य पुलिस को एसआईटी गठन का आदेश दिया है। इस जांच की अंतरिम रिपोर्ट छह सप्ताह के भीतर अदालत को सौंपने के आदेश दिये गये हैं। दरअसल, गत मई में विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद तृणमूल कांग्रेस भारी बहुमत से सत्ता में लौटी। लेकिन दो मई को व्यापक पैमाने पर हिंसा हुई, जिसमें दूसरे राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को निशाना बनाया गया। इसमें जहां चौदह लोगों की हत्या हुई, वहीं महिलाओं से दुराचार जैसे जघन्य अपराध होने के आरोप लगे। राज्य सरकार का रवैया इस मामले पर पर्दा डालने वाला ही रहा। इसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी को मामले की पड़ताल के लिये जांच कमेटी भेजने को कहा था। विडंबना यह रही कि जांच कमेटी पर भी हमले हुए। राज्य पुलिस का रवैया शुरू से ही राजनीतिक दबाव के चलते मामले पर पर्दा डालने वाला ही रहा। अपराधियों को दंडित करने के लिये जो साक्ष्य उपलब्ध थे, उन्हें भी नहीं जुटाया गया। राज्य सरकार के ढुलमुल रवैये के चलते कई बार राज्यपाल जगदीप धनकड़ को सख्त टिप्पणियां करनी पड़ीं। नि:संदेह आरोपों-प्रत्यारोपों के राजनीतिक निहितार्थ भी हैं, जिसमें भाजपा की हार की हताशा भी शामिल है, लेकिन यदि किसी के साथ राजनीतिक दुराग्रह के चलते अन्याय हुआ है तो उसे न्याय दिलाना राज्य सरकार का दायित्व भी है। राजनीतिक रंजिश के चलते दूसरे दल के समर्थकों व कार्यकर्ताओं को निशाना बनाना लोकतंत्र की भावना के खिलाफ ही है। असल बात तो यह है कि इस घटनाक्रम की जांच व कार्रवाई का मामला इतना लंबा नहीं खिंचना चाहिए था।

जाहिरा बात है कि अदालत द्वारा मामले की जांच सीबीआई से करवाने के आदेश से राज्य सरकार नाखुश होगी। दरअसल, सीबीआई पर केंद्र सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगता रहा है। तृणमूल कांग्रेस के नेता दलील दे रहे हैं कि कानून-व्यवस्था राज्य सरकार का मामला है, इसमें केंद्रीय एजेंसियों को दखल नहीं देनी चाहिए। बहुत संभव है कि राज्य सरकार इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे। यानी पीड़ितों को न्याय मिलने में और विलंब होगा जो कि दुराचार जैसे जघन्य अपराधों से पीड़ितों के साथ अन्याय ही होगा। न्यायिक प्रक्रिया से इतर इस मामले में कई गंभीर सवाल भारतीय लोकतंत्र के सामने भी हैं। आखिर आजादी के सात दशक के बाद भी किसी दल की हार-जीत के बाद हिंसा क्यों होती है। हिंसा को कौन बढ़ावा देता है सरकारें उस पर पर्दा डालने की कोशिश क्यों करती हैं पश्चिम बंगाल में निकाय चुनावों से लेकर आम चुनावों तक इतनी राजनीतिक हिंसा क्यों होती है इसमें राजनीतिक दलों की क्या भूमिका होती है। निस्संदेह हिंसा का मतलब लोकतांत्रिक मूल्यों व परंपराओं को नकारना ही है। इसके अलावा कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई जांच के आदेश के बाद जिस तरह की प्रतिक्रिया राजनीतिक दलों द्वारा दिखायी जा रही है, वह भी अनुचित ही है। अभी जांच के आदेश ही हुए हैं, जांच के परिणाम नहीं आये हैं। इसलिये पश्चिम बंगाल सरकार को निशाने पर नहीं लिया जा सकता। निश्चय ही इस विवाद के राजनीतिक निहितार्थ भी हैं। लेकिन राजनीतिक हिंसा में शामिल लोगों को बचाने की किसी भी राज्य सरकार की कोशिश को भी कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। हालांकि, इस जांच के विरोधाभासी परिणाम भी सामने आ सकते हैं क्योंकि एक जांच केंद्रीय एजेंसी करेगी, वहीं दूसरी जांच राज्य सरकार के अधीन आने वाली पश्चिम बंगाल पुलिस। बहरहाल, केंद्रीय एजेंसी व राज्य पुलिस को अपनी विश्वसनीयता बनाये रखते हुए पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में काम करना चाहिए।

भारत की नई तकनीकी चुनौती

मुद्दा

अरविंद मिश्रा

नौ किसी व्यक्ति या समुदाय के जीवन में गुणवत्ता प्रदान करने में डिजिटल सेवाओं की महती भूमिका है। कोरोना काल की पूर्णबंदी ने नागरिक सशक्तिकरण में डिजिटल सेवाओं की भागीदारी को और पुष्ट किया है। डिजिटल तंत्र पर नागरिक सेवाओं की उपलब्धता बढ़ रही है। लेकिन आय, उम्र, लिंग, शिक्षा और भौगोलिक आधार पर डिजिटल सेवाओं में असंतुलन भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। आभासी दुनिया के विस्तार के साथ डिजिटल विषमता हर व्यक्ति और संस्थान के समक्ष चुनौती के रूप में सामने है। ऑनलाइन शिक्षा के मौजूदा दौर में शहरों से लेकर गांवों तक ऐसे बच्चों की तादाद काफी बढ़ी है जो ई-शिक्षा से सिर्फ इसलिए वंचित हैं क्योंकि उनके पास डिजिटल सुविधाएं नहीं हैं। इसी तरह एक बड़ा अनुपात उन बच्चों का भी है जिनके पास डिजिटल सुविधाएं होने के बाद भी उसके इस्तेमाल की जानकारी का घोर अभाव है।

ऐसा नहीं है कि यह संकट सिर्फ ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था के सामने है। मेहनतकश मजदूर और असंगठित क्षेत्र में सक्रिय कार्यबल की डिजिटल अर्थव्यवस्था में उपस्थिति आज भी बहुत ही निचले स्तर पर है। इसमें कोई दो मत नहीं कि डिजिटल सेवाओं की ताकत उसे नागरिक सशक्तिकरण का सबसे सक्षम वाहक बनाती है। ऐसे में डिजिटल अर्थव्यवस्था की चुनौतियों का समाधान डिजिटल समानता के अपेक्षित लक्ष्यों को अर्जित करके ही संभव है। ध्यान रहे कि मोबाइल पर बात करने, संदेश भेजना मात्र ही डिजिटल क्रांति का परिचायक नहीं है। डिजिटल दुनिया तकनीक आधारित संसाधन और सेवाओं के साथ उसकी समझ से आगे बढ़ती है। इसे लोकप्रिय शब्दों में डिजिटल साक्षरता भी कहते हैं। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के मुताबिक डिजिटल साक्षरता का तात्पर्य सूचना और संचार तकनीक के जरिए सूचनाओं के सृजन, विकास और संप्रेषण की उस दक्षता से है जो तकनीकी कौशल व समझ पर केंद्रित हो। यह व्यक्ति और समुदाय के शैक्षणिक, आर्थिक और स्वास्थ्य जरूरतों के साथ ही लोकतांत्रिक अधिकारों को मजबूती प्रदान करती है। यही वजह है कि मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणापत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ ने डिजिटल साक्षरता को बुनियादी जरूरत करार दिया है। आज डिजिटल साक्षरता का क्षेत्र दो तरह की चुनौतियों से जूझ रहा है। पहला, जरूरी डिजिटल परियोजनाओं व साधन का समाज के निचले तबके की पहुंच से दूर होना और दूसरा, डिजिटल सेवाओं के अनुप्रयोग के प्रति जागरुकता का कमी। केंद्र सरकार ने मानसून सत्र के दौरान संसद में बताया कि देश में इंटरनेट उपयोगकताओं की संख्या लगभग बयासी करोड़ है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार अगले दो साल में यह आंकड़ा नब्बे करोड़ के स्तर को पार कर जाएगा। अगले पांच साल में ग्रामीण भारत में शहरों के मुकाबले इंटरनेट उपयोगकताओं की संख्या अधिक होगी। ऐसी परिस्थिति में उभरती हुई जनसांख्यिकी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक टिकाऊ डिजिटल पारिस्थितिक तंत्र तैयार करने की आवश्यकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक डिजिटल इंडिया के फायदे को समाज के निचले तबके तक ले जाने के लिए सबसे पहले डिजिटल परियोजनाओं पर भारी निवेश की जरूरत है। अगर हमें दुनिया की पांच बड़ी डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में शुमार होना है तो पैंतीस अरब डॉलर सालाना निवेश करना होगा। डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में अग्रणी देश अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और जर्मनी जैसे देश अपने सकल घरेलू उत्पाद का एक से डेढ़ प्रतिशत डिजिटल आधारभूत संरचना में निवेश करते हैं। डिजिटल आधारभूत संरचना में निवेश बढ़ा कर एक ऐसा ब्रॉडबैंड आधार विकसित करना होगा जो महानगरों और दूरस्थ गांवों के बीच डिजिटल खाई को पाट सके। मौजूदा डिजिटल अर्थव्यवस्था में शहरी-ग्रामीण, शिक्षित-गैर शिक्षित और लैंगिक असमानता के संकट को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। भारत की भौगोलिक, आर्थिक, जनसांख्यिकी विविधता को देखते हुए डिजिटल सेवाओं को स्थानीय बोली, भाषाओं और सांस्कृतिक परिवेश में ढालना होगा। सामाजिक न्याय का कोई भी प्रयास महिलाओं के बगैर अधूरा रहेगा। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के मुताबिक बारह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की साठ प्रतिशत महिलाओं ने कभी इंटरनेट नहीं चलाया। इसी तरह यूनिसेफ ने अपनी एक रिपोर्ट में डिजिटल साक्षरता के प्रयासों में बच्चों को स्थान नहीं दिए जाने पर चिंता जाहिर की है। यूनेस्को ने समावेशी विकास लक्ष्य-4.1 में इस बात की आशंका जाहिर की है कि डिजिटल साक्षरता में पिछड़ने वाले समुदायों पर विकास के कई प्रतिमानों में पीछे छूटने का खतरा है।

डिजिटल अर्थव्यवस्था में दूरसंचार कंपनियों और बैंकिंग क्षेत्र की एक बड़ी भूमिका है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और दूरसंचार कंपनियों को छोड़ दें तो निजी क्षेत्र के उपक्रमों का ध्यान डिजिटल साक्षरता की ओर नगण्य ही रहा है। सरकारी नीतियों में डिजिटल शिक्षा विशुद्ध रूप से तकनीकी कौशल का विषय प्रतीत होती है। डिजिटल साक्षरता का अनुपात बढ़ाने के लिए आर्थिक सुरक्षा के साथ शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना होगा। एक ऐसा वर्ग जो बुनियादी शिक्षा और आर्थिक सुरक्षा के प्रबंध से वंचित हो उसके लिए डिजिटल साक्षरता कागजी आयोजन से बढ़ कर क्या होगा। समाज के सबसे जरूरतमंद तबके के लिए डिजिटल इंडिया आज भी मोबाइल पर बात करने और स्क्रीन पर तस्वीर देखने की सुविधा तक सीमित है। वर्ष 2015 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू होने के बाद राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन और प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू किया गया। इसमें पंचायत स्तर पर कार्य करने वाली आंगनबाड़ी और आशा कार्यकताओं को डिजिटल कौशल प्रदान किया जाना है। देश में अब तक एक लाख सत्तावन हजार ग्राम पंचायतों को उच्च गति के इंटरनेट की सुविधा प्रदान की गई है। हालांकि सरकार ने मार्च 2020 तक ढाई लाख गांव को भारत नेट ऑप्टिकल फाइबर परियोजना से संबद्ध करने का लक्ष्य रखा था।

जनधन, आधार और मोबाइल आधारित सेवाओं की ही बात करें तो इसके सबसे बड़े हितग्राही गरीबी रेखा से नीचे और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं। जनधन के जरिए चालीस करोड़ से अधिक लोगों को बैंकिंग से जोड़ने का कार्य हुआ है, लेकिन श्रमिकों का एक बड़ा हिस्सा बैंक खाते और आधार से संलग्न मोबाइल नंबर के साथ अपनी संबद्धता लंबे समय तक कायम नहीं रख पाता। इसके पीछे आजीविका के संकट के साथ अन्य जानकारियों की कमी अहम कारक हैं। ऐसे में वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) आधारित सेवाओं का लाभ लेने में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सबसे अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यहां उल्लेखनीय है कि नगद लाभ हस्तांतरण और किसी योजना के हितग्राही के रूप में संबद्ध रहने के लिए आधार व बैंक खाते से संलग्न मोबाइल नंबर की अपरिहार्यता बढ़ती जा रही है। देश में ऑनलाइन बैंकिंग के उपयोगकताओं की संख्या अभी भी पंद्रह करोड़ के स्तर तक नहीं पहुंच पाई है। एक सौ चालीस करोड़ से अधिक की आबादी के लिहाज से यह बहुत आकर्षक आंकड़ा नहीं है। फेसबुक और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पचास प्रतिशत से अधिक उपभोक्ताओं ने ऑनलाइन बैंकिंग के प्रति असंतोष जाहिर किया है। इसमें सबसे बड़ी वजह छिपी हुई दरें, भरोसे की कमी और सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सूचनाओं का विरोधाभासी स्वभाव है।

भगोड़े अफगानी नेतृत्व की लावारिस सेना

दृष्टिकोण

जयसिंह रावत

अफगानिस्तान पर तालिबान के बलात कब्जे और वहां की लावारिस सरकारी सेना के ध्वस्त हो जाने के बाद भारत में सैन्य प्रशिक्षण पा रहे डेढ़ सौ से अधिक अफगान अधिकारियों और जवानों का भविष्य अधर में लटक गया है। इनमें से सर्वाधिक युवा देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी से प्रशिक्षण ले रहे हैं। इस अकादमी से हर छह महीने में लगभग 40 अफगानी युवा अधिकारी पास आउट होकर अपनी सेना का नेतृत्व करते हैं। अमेरिका के साथ ही भारत भी एक सशक्त और आत्मनिर्भर अफगानी सेना को तैयार करने में जुटा था। लेकिन जब राजनीतिक नेतृत्व ही भगोड़ा हो जाये तो फिर मजबूत से मजबूत सेना भी लावारिस हो जाती है।

अफगानिस्तान के अलावा भारत दशकों से भूटान, श्रीलंका, तजाकिस्तान, मालदीव, नेपाल एवं वियतनाम आदि 18 मित्र देशों की सेनाओं के युवा अधिकारियों को प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराता है। बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग के अलावा भारत अफगानिस्तान के सैन्य अधिकारियों को समय-समय पर विभिन्न स्थानों पर विशिष्ट सैन्य प्रशिक्षण भी कराता है ताकि उनका प्रोफेशनल स्तर ऊंचा उठ सके। अफगानिस्तान समेत विभिन्न मित्र देशों के लिये सबसे बड़ी सैन्य प्रशिक्षण सुविधा देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में उपलब्ध है। यहां एनडीए से आने वाले कैडेटों के लिए एक साल और सीधे प्रवेश करने वालों के लिये 18 महीने का कठोर प्रशिक्षण दिया जाता है। यद्यपि आईएमए की सभी पासिंग आउट या दीक्षान्त परेडों का रिकार्ड फिलहाल उपलब्ध नहीं हो सका, फिर भी अकादमी द्वारा जारी पिछली कुछ परेडों की विज्ञप्तियों के अनुसार दिसम्बर 2014 की शीतकालीन परेड में अफगानिस्तान के 44 जैंटलमैन कैडेट अकादमी से प्रशिक्षित होकर पास आउट हुए। इसी प्रकार जून 2015 की ग्रीष्मकालीन परेड में भी 44, दिसम्बर, 2018 में 49, दिसम्बर 2020 में 41 और जून 2021 की दीक्षान्त परेड में 43 युवा अफगानी अधिकारी अकादमी से पास आउट हुए। आईएमए के अलावा भारत की इलीट सैन्य प्रशिक्षण अकादमी एनडीए खड़कवासला से भी अफगानी युवा सैन्य प्रशिक्षण के साथ ही ग्रेजुएशन प्राप्त करते हैं।

भारत में सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे इन युवा सैन्य अधिकारियों का भविष्य तो अधर में लटक ही गया, लेकिन अफगानिस्तान में जान बचाने के लिये मची भगदड़ ने उनके परिवारों की खैरियत को लेकर उनकी बेचैनी बढ़ा दी है। उनकी चिन्ता का सबसे बड़ा कारण तालिबान का अफगानिस्तान की सरकारी सेना के प्रति नफरत और उनका क्रूरतम व्यवहार है। अब इनका भविष्य भारत सरकार के अगले कदम पर निर्भर है। अगर उनका प्रशिक्षण जारी रखा जाता है तो प्रशिक्षण पूरा होने पर भी उनका भविष्य अधर में है।

भारत ने अफगानिस्तान की सेना को सशक्त बनाने के लिये 4 एमआई-25 सशस्त्र हेलीकाप्टर एवं 3 चीता हेलीकाप्टर सहित काफी आधुनिक सैन्य साजो सामान दे रखा है। भारत अफगानिस्तान के सशस्त्र बलों को आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण भी देता रहा है। अफगानी युवा अधिकारियों को इन्फेंट्री स्कूल में यंग आफिसर्स कोर्स और मिजोरम के वैरेंग्टे स्थित संस्थान में जंगल वारफेयर और आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण भी देता रहा है। ऐसे विशिष्ट संस्थानों में प्रति वर्ष लगभग 700 से लेकर 800 तक अफगानी सैन्यकर्मी प्रशिक्षण पाते रहे हैं। यह भी सवाल है कि क्या हमारी मेहनत और मदद अकारथ गयी पिछले महीने अफगानिस्तान के सेना प्रमुख जनरल वली मोहम्मद अहमदजई का भारत के साथ और अधिक सैन्य सहयोग बढ़ाने के इरादे से भारत आने का कार्यक्रम था, लेकिन तालिबानियों के बढ़ते खतरे को देखते हुए उन्हें अपना दौरा स्थगित करना पड़ा। भारत के साथ ही अमेरिका ने भी अफगानी सेना को मजबूत, आत्मनिर्भर और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिये तैयार करने पर अरबों डालर खर्च किए हैं। न्यूयार्क टाइम्स में 13 अगस्त को छपी थॉमस जिब्बन, फहीम अबेद और शैरिफ हसन की साझा रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने पिछले दो दशकों में अफगानिस्तान की सुरक्षा के लिये हथियारों, अत्याधुनिक उपकरणों और प्रशिक्षण पर 83 अरब डॉलर से अधिक राशि खर्च कर डाली। लेकिन वहां के राजनीतिक नेतृत्व की कमजोरी के कारण अफगानी सैनिकों ने तालिबानियों के आगे हथियार डाल दिये, जिस कारण अरबों डालर मूल्य के अत्याधुनिक हथियार भी तालिबान के हाथ लग गये। वहां लगभग 3 लाख की सरकारी सेना लड़ती भी तो किसके लिये

सैन्य प्रशिक्षुओं की भांति भारत में स्कॉलरशिप के आधार पर पढ़ रहे छात्रों के समक्ष भी गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। छात्रों के अलावा विभिन्न अन्य क्षेत्रों में आपसी सहयोग के अन्तर्गत कार्यरत या प्रशिक्षणरत अफगानी विशेषज्ञों का भविष्य भी अधर में लटका हुआ है। फिर भी फिलवक्त वहां तालिबान ही तालिबान है, इसलिये भारत की विदेश नीति और कूटनीति दोनों के लिये परीक्षा की घड़ी है।

आजकल

अभाव की खुराक

सभी राज्यों में टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा है। कई सरकारें टीकाकरण में अव्वल आने की होड़ करती देखी जा रही हैं। पिछले दिनों टीकों की कमी को लेकर खासी राजनीति भी हुई थी, पर अब वह शांत है। अपने देश में बने दो टीकों के अलावा बाहर से भी तीन टीके मंगाए गए हैं। इन सबके बावजूद स्थिति यह है कि देश में तीन करोड़ चालीस लाख से ऊपर लोग ऐसे हैं, जिन्हें पहली खुराक दी जा चुकी है, पर तय अवधि पार हो जाने के बाद भी वे दूसरी खुराक अब तक नहीं ले पाए हैं। इसे लेकर स्वाभाविक ही चिंता जताई जाने लगी है कि ऐसे लोगों में प्रतिरोधक क्षमता कितनी मजबूत रह पाएगी।

हालांकि कई चिकित्सक कहते रहे हैं कि दोनों टीकों के बीच अधिक अंतर रखना प्रतिरोधक क्षमता के लिहाज से बेहतर नतीजे देगा। इसी आधार पर जब टीकों की कमी को लेकर शोर मचना शुरू हुआ, तो चार हफ्ते से बढ़ा कर दोनों के बीच का अंतर आठ से बारह हफ्ते कर दिया गया था। कोविशील्ड के लिए दूसरी खुराक की अवधि चौरासी से एक सौ बारह दिन और कोवैक्सीन के लिए अट्ठाईस से बयालीस दिन कर दी गई। माना गया था कि दोनों खुराकों के बीच की अवधि बढ़ने से टीकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने में आसानी होगी। मगर यह सच साबित होता नजर नहीं आ रहा। हालांकि सरकार का दावा है कि टीकों की कोई कमी नहीं है। पर यह सवाल अपनी जगह बना हुआ है कि करीब साढ़े तीन करोड़ लोग दूसरी खुराक क्यों नहीं ले पाए हैं। यह ठीक है कि टीका लगवाने के मामले में अब भी बहुत सारे लोगों के मन में हिचक और अविश्वास बना हुआ है। बहुत समझाने के बावजूद वे टीके लगवाने को तैयार नहीं हो रहे। यह एक समस्या तो है ही, पर जो पहली खुराक ले चुके हैं, उनके बारे में यह नहीं माना जा सकता कि वे दूसरी खुराक को लेकर लापरवाही बरत रहे होंगे। इससे यही जाहिर है कि टीकाकरण अभियान में पहली खुराक देने को लेकर जितनी तेजी दिखाई जा रही है, उतनी ही तत्परता शायद दूसरी खुराक को लेकर नहीं दिखाई जा रही। टीके और टीकाकरण केंद्रों की कमी भी अभी दूर नहीं हो पाई है। यह शिकायत बहुत सारे लोग करते मिल जाते हैं। कोविन ऐप पर दूसरी खुराक के लिए पंजीकरण करने जाएं, तो स्पष्ट लिखा मिलता है कि कोई टीकाकरण केंद्र उपलब्ध नहीं। यही वजह है कि पहली खुराक ले चुके बहुत सारे लोग दूसरी खुराक नहीं लगवा पा रहे। सरकारें टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के जो आंकड़े बढ़-चढ़ कर पेश कर रही हैं, वे दरअसल, पहली खुराक के हैं। शायद सरकारों ने मान लिया है कि टीकाकरण का मतलब पहली खुराक दे देना ही है। मगर इस तरह न तो टीकाकरण का मकसद पूरा हो पाएगा और न कोरोना से लड़ने में मदद मिल पाएगी।

'संस्कृत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी'

संस्कृत सप्ताह पर विशेष

खगोल विज्ञान भारत में ही विकसित हुआ। प्रसिद्ध जर्मन खगोलविज्ञानी कॉपरनिकस से लगभग 1000 वर्ष पूर्व आर्यभट्ट ने पृथ्वी की गोल आकृति और इसके अपनी धुरी पर घूमने की पुष्टि कर दी थी। इसी तरह आइजक न्यूटन से 1000 वर्ष पूर्व ही ब्रह्मगुप्त ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण सिद्धान्त की पुष्टि कर दी थी। यह एक अलग बात है कि किन्हीं कारणों से इनका श्रेय पाश्चात्य वैज्ञानिकों को मिला। वैदिककालीन भारतीय के लोग धर्मानुकूल थे।

भारतीय विज्ञान की परंपरा विश्व की प्राचीनतम वैज्ञानिक परंपराओं में एक है। भारत में विज्ञान का उद्भव ईसा से 3000 वर्ष पूर्व हुआ है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त सिंधु घाटी के प्रमाणों से वहाँ के लोगों की वैज्ञानिक दृष्टि तथा वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोगों का पता चलता है। प्राचीन काल में चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में चरक और सुश्रुत, खगोल विज्ञान व गणित के क्षेत्र में आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट द्वितीय और रसायन विज्ञान में नागार्जुन की खोजों का बहुत महत्त्वपूर्ण योगदान है। इनकी खोजों का प्रयोग आज भी किसी-न-किसी रूप में हो रहा है।

भारतीय विज्ञान का विकास प्राचीन समय में ही हो गया था। अगर यह कहा जाए कि भारतीय विज्ञान की परंपरा दुनिया की प्राचीनतम परंपरा है, तो अतिशयोक्ति न होगी। जिस समय यूरोप में घुमक्कड़ जातियाँ अभी अपनी बस्तियाँ बसाना सीख रही थीं, उस समय भारत में सिंध घाटी के लोग सुनियोजित ढंग से नगर बसा कर रहने लगे थे। उस समय तक भवन-निर्माण, धातु-विज्ञान, वस्त्र-निर्माण, परिवहन-व्यवस्था आदि उन्नत दशा में विकसित हो चुके थे। फिर आर्यों के साथ भारत में विज्ञान की परंपरा और भी विकसित हो गई। इस काल में गणित, ज्योतिष, रसायन, खगोल, चिकित्सा, धातु आदि क्षेत्रों में विज्ञान ने खूब उन्नति की।

आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, बोधायन, चरक, सुश्रुत, नागार्जुन, कणाद से लेकर सवाई जयसिंह तक वैज्ञानिकों की एक लंबी परंपरा विकसित हुई।

खगोल विज्ञान भारत में ही विकसित हुआ। प्रसिद्ध जर्मन खगोलविज्ञानी कॉपरनिकस से लगभग 1000 वर्ष पूर्व आर्यभट्ट ने पृथ्वी की गोल आकृति और इसके अपनी धुरी पर घूमने की पुष्टि कर दी थी। इसी तरह आइजक न्यूटन से 1000 वर्ष पूर्व ही ब्रह्मगुप्त ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण सिद्धान्त की पुष्टि कर दी थी। यह एक अलग बात है कि किन्हीं कारणों से इनका श्रेय पाश्चात्य वैज्ञानिकों को मिला।

वैदिककालीन भारतीय के लोग धर्मानुकूल थे। वे अपने यज्ञ तथा अन्य धार्मिक अनुष्ठान ग्रहों की स्थिति के अनुसार शुभ लग्न देखकर किया करते थे। शुभ लग्न जानने के लिए उन्होंने खगोल विज्ञान का विकास किया था। वैदिक आर्य सूर्य की उत्तरायण और दक्षिणायन गति से परिचित थे। वैदिककालीन खगोल विज्ञान का एक मात्र ग्रंथ 'वेदांग ज्योतिष' है। इसकी रचना 'लगध' नामक ऋषि ने ईसा से लगभग 100 वर्ष पूर्व की थी। महाभारत में भी खगोल विज्ञान से संबंधित जानकारी मिलती है। महाभारत में चंद्रग्रहण और सूर्यग्रहण की चर्चा है। इस काल के लोगों को ज्ञात था कि ग्रहण केवल अमावस्या और पूर्णिमा को ही लग सकते हैं। इस काल के लोगों का ग्रहों के विषय में भी अच्छा ज्ञान था। 'वेदांग ज्योतिष' के बाद लगभग एक हजार वर्षों तक खगोल विज्ञान का कोई ग्रंथ नहीं मिलता।

प्राचीन काल में भारत में अन्य विज्ञानों के साथ-साथ भौतिकी का भी प्रचलन था। कणाद ऋषि ने छठी शताब्दी ईसा पूर्व ही इस बात को सिद्ध कर दिया था कि विश्व का हर पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है। उन्होंने परमाणुओं की संरचना, प्रवृत्ति तथा प्रकारों की चर्चा की है।

प्राचीन भारत के ही एक प्रसिद्ध गणितज्ञ और ज्योतिषी भास्कराचार्य जी ने गुरुत्वाकर्षण शक्ति की खोज की थी, कालांतर में जिसे पूरी दुनिया ने जाना। संस्कृत की दर्शन परंपरा में संसार में सर्वाधिक चिंतन मनन हुआ। इसी दर्शन परंपरा में महान दार्शनिक कपिलमुनि ने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया। ऋषि कणाद वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे। उन्होंने भौतिक विज्ञान पर भी काम किया और उनका परमाणु आविष्कार प्रसिद्ध है।

(नरोत्तम मिश्रा, लेखक म.प्र. शासन के गृहमंत्री)